What I want the hon. House to realise is this; if you want to oppose, oppose on principle. In this case, the opposition should be that MPs are entitled to a privilege and they should continue to have it. Okay. That is a point of view. Or you can say that MPs should not have the privilege and they should be subjected to the same taxation as the rest of the people. That is the other point of view—that is my point of view.

The hon. member may have a very small income and he will not be paying tax. I am not a fraud or humbug to say that I do not pay tax. I am paying 97 per cent tax. I am proud of it. Probably in five years, I will have nothing to pay. That is the taxation structure in the country.

I have worked it out. As against approximately Rs. 6,000 I draw as allowance from Parliament, I would have to earn almost Rs 2½ lakhs to clear Rs. 6,000 which should be the normal case if the allowance-income attracted income-tax. That is the taxation.

Therefore, I feel that the man in the street and the Members of Parliament should be subject to the same taxation and we do not want double yardsticks. I am quite sure that Parliament is not at any stage adverse to the fact that they should be subject to the same tax burdens.

Take the privileges. I would like to be clear in my mind that it is not my desire that at any stage the functioning of an MP, to discharge his duties, should be hampered. That is not my intention. But I do feel that taxation is something that applies to all Indians. Therefore, there should be some uniformity.

With this, I conclude my remarks. If the hon. House in its wisdom continue, throw the Bill out.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954".

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Leave is refused.

SHRI MURASOLI MARAN (Madras South): On a point of order. There has been a convention in this House that no Private Member's Bill has ever been opposed at the introduction stage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is not a convention; it is the pleasure of the House to give leave or not to give leave.

---

**15.44 hrs.**

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

*(Amendment of Seventh Schedule)*

**श्री भोगेन्द्र झा** (जयनगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India"

*The motion was adopted.*

**श्री भोगेन्द्र झा** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

---

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

*(Amendment of arts. 100 and 189)*

SHRI R. P. ULAGANAMBI (Vellore): I beg to move for leave to introduce

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 23-2-72.

[Shri R. P. Ulaganambi]

a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India".

*The motion was adopted.*

SHRI R. P. ULAGANAMBI: introduce the Bill.

---

**15.45 hrs.**

## CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*contd.*

*(Amendment of Eighth Schedule)* by Dr. Karni Singh

MR. DEPUTY-SPEAKER: We now take up further consideration of the following motion moved by Dr. Karni Singh on the 15th December, 1972:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration".

as also further consideration of amendment for circulation of the Bill for the purpose of eliciting opinion thereon, moved by Shri M. C. Daga on the 15th December 1972.

Shri S. N. Singh was on his feet on the last occasion.—He is not here.

Shri Onkarlal Berwa.

**श्री ओंकार लाल बेरवा** (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस भाषा का विरोध नहीं करता, क्योंकि राजस्थान का रहने वाला हूं। लेकिन विरोध इस लिये करता हूं कि जिन्होंने इसे भाषा के रूप तो यहां रखा है, उन्होंने भी अंग्रेजी में रखा है। अच्छा होता कि वह राजस्थानी में बोलते, उस से मुझे खुशी होती। लेकिन जब से यह बिल यहां रखा गया और उस पर जितने भाषण इस सभा में हुए सब ने विदेशी भाषा में अपने विचार प्रकट किए। इस लिये हम जो राजस्थानी भाषा बोलने वाले हैं, हम यह महसूस करते हैं कि यह सब हिन्दी के साथ फैक्शन बढ़ाने के लिये किया गया है। हिन्दी भाषा एक मात्र ऐसी भाषा है जोकि सारे देश के लिए है। हिन्दी हमारी मातृ-भाषा है लेकिन यह उसको उस स्थान से अलग हटाना चाहते हैं। राजस्थान में मारवाडी, मेवाड़ी, कोटा, बूंदी की भाषायें हैं। रेडियो प्रोग्राम में भी मारवाड़ी को घुसेड रखा है। मैं कहता हूं हड़ौती भाषा है उसको भी रेडियो प्रोग्राम में स्थान क्यों नहीं मिलना चाहिए। तीन महीने मारवाड़ी, तीन महीने मेवाड़ी और तीन महीने हड़ौती—इस प्रकार से चलना चाहिए। मेरा कहना है कि भाषाओं की उन्नति इस प्रकार से नहीं हुआ करती। राजस्थान जब से बना उसको पहले अलग-अलग राज्यों में बंटा हुआ था तो वहां पर कितने स्कूल कालेज बने? कितना वहां पर अनुदान दिया गया। आज राजस्थान को हिन्दी से विच्छेद करने के लिए यह रेजोल्यूशन लाया गया है, हम इसका डटकर विरोध करेंगे। राजस्थान की भाषा हिन्दी ही होनी चाहिए। राजस्थानी भाषा हम जरूर बोलें, बोलते भी हैं और आगे भी बोलेंगे लेकिन अलग शाखा के रूप में रखने का कोई प्राविधान नहीं है न होना ही चाहिए। इसका हम डटकर विरोध करेंगे।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** (निजामाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थानी और हिन्दी दोनों अलग-अलग भाषायें हैं। . . . (**व्यवधान**) . . . यह कहना कि हिन्दी के विरोध में राजस्थानी भाषा का प्रस्ताव यहां पर लाया गया है यह बिल्कुल गलत होगा। दो भाषायें अलग अलग हैं। अगर पार्लियामेण्ट चाहे तो इसको स्वीकार कर सकती है या चाहे तो रद्द कर सकती है। लेकिन यहां पर यह कहना कि हिन्दी को धक्का लगाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है यह बिल्कुल गलत होगा। . . . (**व्यवधान**) . . . मैं एक दक्षिण प्रदेश का रहने वाला हूं लेकिन फिर भी मैं हिन्दी का चाहने वाला हूं। आप देख रहे हैं मैं हमेशा हिन्दी में बोलने की कोशिश करता हूं। हिन्दी इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसकी भी मैं तारीफ करता हूं। अंग्रेजी की जगह पर हिन्दी होनी चाहिए, यह मैं चाहता हूं। लेकिन